पंचायती राज मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3122
दिनांक 20.08.2025 को उत्तरार्थ

नागालैंड में ई-गवर्नेंस पहल

3122. श्रीमती एस. फान्गनॉन कोन्याक:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(**क**) नागालैंड में ग्राम परिषदों के लिए ई-गवर्नेंस पहल में क्या प्रगति हुई है; और

(**ख**) नागालैंड की ग्राम परिषदों में डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो**.** एस**.**पी**.**सिंह बघेल**)**

(**क**) **और** (**ख**)पंचायती राज मंत्रालय, नागालैंड सहित देश भर में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में ई-गवर्नेंस को मज़बूत बनाने के लिए, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का क्रियान्वयन कर रहा है। राज्य की सभी ग्राम परिषदों को ऑनलाइन योजना, बजट, लेखा, निगरानी और रिपोर्टिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत विकसित ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन उपलब्ध कराया गया है। इसे प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए राज्य और स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने नागालैंड सहित पूरे देश में ई-ग्रामस्वराज-सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) इंटरफ़ेस शुरू किया है, ताकि संबंधित ग्राम परिषदों के बैंक खातों से लाभार्थियों/ठेकेदारों को केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग के अनुदानों का सीधा ऑनलाइन हस्तांतरण संभव हो सके। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और मैन्युअल प्रक्रिया को कम करना है। ग्राम परिषदों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है, और डिजिटल लेनदेन को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण पहल की जा रही है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य की 1,320 ग्राम परिषदों में से 977 ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफ़ेस सेजुड़(भुगतान करने के लिए तैयार) चुकी हैं।

*****